

अध्याय-4 (Vol-2)

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

Monetary Management and Financial Intermediation

प्रस्तावना:

- मौद्रिक नीति वर्ष 2019-20 में उदार बनी रही। धीमी गति से विकास और नरितर मुद्रास्फीति के कारण उक्त वित्त वर्ष में मौद्रिक नीति समिति की लगातार चार बैठकों में रेपो दर में 110 आधार अंकों की कटौती की गई। हालाँकि दिसंबर 2019 में आयोजित पाँचवी बैठक में इसे अपरवर्तित रखा गया है।
- वर्ष 2019 में मार्च से सितंबर के बीच अनुसूचित वाणज्यिक बैंकों का सकल अनषिपादक अग्रमि अनुपात 9.3% पर अपरवर्तित रहा तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय नगिर्मों के संबंध में यह मामूली वृद्धि के साथ मार्च 2019 के 6.1% से बढ़कर सितंबर, 2019 में 6.3% हो गया।

वर्ष 2019-20 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम:

- वर्ष 2019-20 के दौरान मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन संशोधित सांघिकि रूपरेखा के अधीन किया गया जो कि 27 जून, 2016 को लागू हुई।
- दिसंबर 2019 में अपने पाँचवें द्वमिसिकि मौद्रिक नीतिगत वविरण में रेपो दर को 5.15% पर अपरवर्तित रखने का नरिणय RBI द्वारा किया गया।

तरलता (नकदी) की स्थिति और इसका प्रबंधन:

- वर्ष 2019-20 में प्रणालीगत तरलता जून 2019 से काफी हद तक अधशेष में रही है।
- सांघिकि नकदी अनुपात (Statutory Liquidity Ratio-SLR) में चार चरणों में प्रत्येक बार 25 आधार बढि दर (BPS) की कमी की गई जो क्रमशः 13 अप्रैल 2019, 6 जुलाई 2019, 12 अक्तूबर 2019 तथा 4 जनवरी 2020 से प्रभावी हुई जिससे बैंकों की 'शुद्ध मांग और सावधकि उत्तरदायतिव' (Net Demand and Time Liabilities- NDTL) में 18.25% की वृद्धि हुई है। यह दिसंबर 2018 में घोषित रूपरेखा के अनुसार है जिसका लक्ष्य है SLR को तरलता व्याप्ति अनुपात (LCR) से साथ एकरूप करना।

सरकारी प्रतभूत बाजार घटनाक्रम:

- वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के दौरान 10 वर्ष के सरकारी प्रतभूत भिानकों के लाभ प्राप्ति में कमी देखने को मली है।
- इसका मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों की कमी, अधशेष तरलता और लगातार चार नीतिगत दरों में कटौती की मात्रा (जो 110 BPS है) में कमी है।
- आरबीआई द्वारा 'स्पेशल मार्केट आपरेशन' जिसका अर्थ दीर्घकालिक प्रतभूतियों की खरीद और साथ ही लघु अवधकि प्रतभूतियों की बकिरी था, ने दस साल की सरकारी प्रतभूत पर लाभ प्राप्ति को नीचे लाने में सहायता की। इससे दीर्घ और अल्प अवध के बॉड लाभ प्राप्ति के बीच अंतर को कम करके लाभ प्राप्ति वक्र में सुधार लाने की उम्मीद बनी।
- पहले दौरे में 10000 करोड़ रुपए मूल्य की बकिरी एवं खरीद की गई। जिससे 23 दिसंबर, 2019 को पूरा किया गया। दूसरा और तीसरा दौर क्रमशः 30 दसिम्बर, 2019 और 6 जनवरी, 2020 को इसी राशकि लिये पूरा किया गया था। इसकी वजह से दस साल की सरकारी प्रतभूत की लाभ प्राप्ति में मामूली गरिवट आई।

बैंकिंग क्षेत्र:

- अनुसूचित वाणज्यिक बैंकों का सकल गैर-नषिपादति अग्रमि अनुपात प्रतशित के रूप में जी.एन.पी.ए. का सकल गैर नषिपादति अग्रमि अनुपात सितंबर 2019 के अंत में 9.3% पर समान बना रहा जैसा कि मार्च 2019 के अंत में था। इसी प्रकार उसी अवध में उनका पुनर्गठति मानक अग्रमि अनुपात 0.4% पर अपरवर्तित रहा।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पूंजी एवं जोखमि भारति परसिंपदा अनुपात (Capital to Risk-Weighted Asset Ratio-CRAR) मार्च 2019 से सितंबर 2019 के बीच 14.3% से बढ़कर 15.1% तक देखा गया।

मौद्रिक संचरण:

- मौद्रिक संचय का प्रसारण वर्ष 2019 में तीनों स्तरों (दर संरचना, साख वृद्धि और आवधिक संरचना) पर कमजोर रहा।

a) दर संरचना:

- अनुसूचित वाणज्यिक बैंकों की भारति औसत उधार दर (Weighted Average Lending Rate- WALR) में जनवरी 2019 से 135 BPS की रेपो दर में कमी होने के बावजूद वर्ष 2019 में कोई गरीवट देखने को नहीं मली।
- जनवरी 2019 में अनुसूचित वाणज्यिक बैंक का WALR 10.38% था और अक्टूबर, 2019 में 10.40% है।

b) साख वृद्धि:

- पॉलिसी दरों में कमी आने के बावजूद अर्थव्यवस्था में इस वर्ष की शुरुआत से ही साख वृद्धि में गरीवट रही है।
- बैंक क्रेडिट वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) अप्रैल 2019 में 12.9% से सामान्य होकर 20 दसिंबर, 2019 तक 7.1% हो गई।

c) आवधिक संरचना:

- RBI की मौद्रिक सुगमता और एलएएफ तरलता का प्रभाव अल्पकालीन ब्याज दरों पर नरिभर रहा है कति इस कषतकी भरपाई दीर्घकालिक परपिकवता के माध्यम से नहीं हो रही है। क्योंकि इस वर्ष की शुरुआत में अल्पकालिक सरकारी प्रतभूतियों (364 दनि वाले T-Bills) के प्रतफल में कमी दीर्घकालिक सरकारी प्रतभूतियों (10 वर्ष) की तुलना में काफी तेज़ गति से हुई।
- RBI द्वारा वशीष खुले बाजार संचालन द्वारा प्रकरिया में बदलाव करने के बाद छुट-पुट कमी को छोड़कर वास्तव में अगस्त 2019 के बाद 10 वर्ष वाली सरकारी प्रतभूति के प्रतफल में अधिक कमी नहीं आई है।

गैर बैंकगि वत्तीय कषेत्र (NBFC):

- वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 की अर्द्ध छमाही में अततेजी से बढ़ने के बाद इस कषेत्र में अवमंदन की स्थिति देखने को मली है।
- गैर बैंकगि वत्तीय नगिमां से ऋणों की वृद्धि सतिंबर 2018 में 27.6%, दसिंबर 2018 में 21.6% से सतिंबर 2019 के अंत में गरिकर 9.9% रही है।

गैर-बैंकगि वत्तीय वनियिमन/पर्यवेक्षण से संबधति मुख्य नीतगित परविरतन:

- NBFC सेक्टर के वनियिमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लयि भारतीय रज़िर्व बैंक अधनियिम, 1934 में संशोधन ताकरिज़िर्व बैंक में अतरिकित शक्तियाँ नहिति की जा सकें।
- **अधिकृत डीलर के रूप में योग्य एनबीएफसी-एनडी-एसआई-द्वत्तीय श्रेणी:** रज़िर्व बैंक ने जनता को अपने दैनिकि गैर-व्यापार चालू खाता लेन-देन के लयि प्रदान की गई सेवाओं की पहुँच एवं दक्षता बढ़ाने के लयि 16 अप्रैल, 2019 से गैर-डिपॉजिट लेने वाली प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण एनबीएफसी-आईसीसी को ए डी-द्वत्तीय श्रेणी अनुज्ञपत्ति/लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दी है।
- NBFC के लयि तरलता जोखमि ढाँचा।
- NBFC-सूक्ष्म वत्तीय संस्थाओं (NBFC-MFI) के लयि सीमाओं की समीक्षा करना।

वदिशी पोर्टफोलयो नविश (FPI) द्वारा नविश :

- अप्रैल-दसिंबर, 2019 के दौरान भारतीय पूंजीगत बाजार में FPI के संदर्भ में नविल आमद 0.81 लाख करोड़ रुपए थी जबकि अप्रैल-दसिंबर 2018 के दौरान में यह 0.94 लाख करोड़ रुपए थी।
- 31 दसिंबर, 2019 तक FPI द्वारा कुल संचति नविश (240.1 बलियिन यूएस डॉलर) में 7.8% की बढ़ोत्तरी के साथ यह 259.5 बलियिन यूएस डॉलर पहुँच गया।

बीमा कषेत्र:

- अंतरराष्ट्रीय रूप से बीमा कषेत्र की संभावना एवं नषिपादन क्षमता के मूल्यांकन को सामान्यत: दो मापकों (बीमा संबंधी नविश व बीमा संबंधी सघनता) के आधार पर मापा जाता है।
- भारत में बीमा संबंधी सघनता वर्ष 2001 में 11.5 अमेरिकी डॉलर थी जो वर्ष 2018 में 74 अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई (जीवन बीमा- 55 अमेरिकी डॉलर और गैर जीवन बीमा-19 अमेरिकी डॉलर)।
- 12.47% की वृद्धि दर करते हुए वर्ष 2018-19 के दौरान गैर-जीवन बीमति कषेत्र का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम पछिले वत्तीय वर्ष 2017-18 में 1.51 लाख करोड़ रुपए की तुलना 1.69 लाख करोड़ रुपए था।
- 10.75% की वृद्धि दर करते हुए जीवन बीमा उद्योग ने पछिले वत्तीय वर्ष में 4.59 लाख करोड़ रुपए की तुलना वत्तीय वर्ष 2018-19 में 5.08

लाख करोड़ रुपए की प्रीमियम आय दर्ज की ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/economy-survey-vol-2-2019-chapter-4>

